सम्पादक के नाम

तुम्हे मिले थे 31% वोट, तुम्हारे खिलाफ गए थे 69% वोट

2014 के आम चुनाव की बात कर रहा हूँ. ओवरऑल तुम्हें 31% वोट मिले, तुमने सरकार बना ली. तुम्हारे खिलाफ 69% वोट पड़ा. लेकिन वो संगठित नहीं था बिखरा हुआ था, टुकड़ों में था. लेकिन था तो तुम्हारे खिलाफ ही न. तुमने बता दिया लहर है, सुनामी है, तूफ़ान है, 56 इंची है, शेर है, बगैरह बगैरह. सही है न ?

फिर तुमने उन 69% को देशद्रोही बोलना शुरू कर दिया उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात करने लगे. है न ? कभी अराजक बोला, कभी नक्सली बोला, कभी गुलाम बोला, कभी विदेशी बोला, कभी 70 साल बोला, कभी नेहरू बोला, कभी गांधी बोला, कभी पद्मावत ले आये, कभी गोडसे तो कभी जिन्ना ले आये. कभी गंगा तो कभी गाय तो कभी गोबर में कोहिनूर दिखाया, कभी जेएनयू पेला कभी अखलाक ले आये, कभी रोहित बेमुला ले आये, कभी मंदिर ले आये कभी मस्जिद ले आये, अभी अजान तो कभी आरती ले आये, कभी शमशान तो कभी कब्रिस्तान दिखाया, कभी ऊना दिखाया कभी कैराना दिखाया. सही बोल रहा हूँ कि नही ?

अब तुम हनुमान जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था बताने लगे, सीता जी टेस्ट्यूब बेबी थी कहने लगे. लव-कुश राम जी के बच्चे नहीं थे बोलने लगे, अमित शाह कलयुग के राम हैं ये भी बता दिया. महाभारत के समय इंटरनेट था ये भी बता दिया.

रोता किसान नही दिखा, मरता जवान नही दिखा, भटकता नौजवान नहीं दिखा, जीएसटी और नोटबंदी से त्रस्त व्यापारी नहीं दिखा, महंगाई नहीं दिखी, शिक्षा का गिरता स्तर नहीं दिखा, चरमराते अस्पताल नहीं दिखे, बेनामी चन्दा नहीं दिखा, लोकपाल नहीं दिखा.

ये दिखाई दिया है उस 69% को जिसने तुम्हारे खिलाफ मतदान किया था.

आज वो सोचने पर मजबूर है कि हम कब तक टुकड़ो में बंटे रहेंगे यदि हम बिखरे हुए रहेंगे एकजुट नहीं रहेंगे तो तुम 31% हम 69% पर ऐसे है शासन करते रहोगे.

अब वो संगठित हो रहे हैं तो तुम उन्हें कुत्तों का झुंड बोल रहे हो

याद रखना कब कब किस किस को सांप छछूंदर कुत्ता बिल्ली बोला है. ये 69% हैं जो तुम्हे नापसंद करते थे आज इनकी संख्या 69% से बढ़कर 80% हो गयी है.

- साइबर नज़र

90 प्रतिशत भारतीय मूर्ख हैं और ये बात सच भी है

हमारी मूर्खता का पैमाना ये है, कि एक आदमी लाखों का सूट-बूट पहनकर कहता है कि मैं गरीब हूं, झोला लेकर चलता हूँ और हम उसे गरीब मान लेते हैं !

सीबीआई, एनआईए, जैसी एजेंसियां जिस आदमी के हाथों की कठपुतली हैं, वह आदमी कह रहा है कि मुझे सताया जा रहा है और हम मान लेते हैं !

जो संसद मे पूर्ण बहुमत में है, बीस से ज्यादा राज्यों मे सरकार है, वह कहता है, मुझे काम नही करने दिया जा रहा है और हम मान लेते हैं !

जो जेल में रह चुके भ्रष्टाचारी लोगों को टिकट देता है फिर कहता है, मै भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं और हम मान लेते हैं !

जिसके शासन मे सबसे ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, वह कहता है, दुश्मन हमसे कांप रहा है और हम मान लेते हैं !

जिसके समय में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है और वह कहता है, हमने किसानों की आय दुगुना कर दी है और हम मान लेते हैं !

जिसके समय में पढ़े लिखे नौजवानों को पकौड़ा तलने के लिए कहा जाता है और हम उसे रोजगार मान लेते हैं !

जिसके राज्य मे सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं और वह कहता है हम "बेटी बचाओ अभियान" चला रहे हैं और हम मान लेते हैं !

जो सुंदर भविष्य का सपना दिखाकर सत्ता में आया हो और चार सौ साल पहले के भूतकाल में हमे घुमा रहा हो और फिर भी हम खुश हैं !

मित्रों ये सब हमारी मूर्खता की वजह से ही तो हो रहा है !

- यशवंत सिन्हा

पतंजलि के विज्ञापनों पर लार टपकाता मीडिया आपको जो नहीं बताएगा, वह यहाँ पर पढ़ लीजिए.....

उत्तर प्रदेश में भी यही बात हुई है ....सरकारी स्कीम में मनमाने परिवर्तन करिए ओर अधिक से अधिक जमीन पर कब्जा कीजिये ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है।

लाला रामदेव देश के सबसे बड़ा जमीन हड़पने वाले बाबा है। पहले के जमाने मे बाबा छोटे बच्चों को झोले में छिपाकर उठा ले जाते है अब मॉडर्न बाबा बड़े ठसके के साथ देश के हर छोटे बड़े राज्य में जाता है और वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अमले को पटा कर ज़्यादा से ज्यादा जमीन कबाड़ता है, ओर उद्योग लगाने के नाम पर दस तरह के धतकरम करता है।

लाला रामदेव धमकी दे रहे है कि मेगा फ़ूड पार्क को उठा कर दूसरी जगह ले जाएंगे लेकिन सोचने की बात तो ये है कि लेकर जाएगे कहाँ ? उत्तराखंड के हरिद्वार मे तो फ़ूड पार्क चल ही रहा है मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, ओर राजस्थान जैसे राज्यों में तो उन्होंने पहले ही फूड पार्क की नींव रखी है वही अभी पूरे नही हो रहे हैं। और सभी जगह यही सवाल उठेंगे तो आखिर जाएगे कहाँ ?

दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात यह हैं कि जिस मेगा फ़ूड पार्क की बात की जा रही है वह तो मात्र 50 एकड़ में खड़ा किया जाने वाला है तो ये बाकी 405 एकड़ किसलिए इन्हें सस्ती दर पर चाहिए।

ये लाला रामदेव जमीनों के कितना भूखे हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिये कि आज से दो साल पहले जब मध्यप्रदेश सरकार ने इसे मेगा फ़ूड पार्क के लिए पीतमपुर में 45 एकड़ जमीन देने की घोषणा की तो बाबा रामदेव ने इन्वेस्टर समिट के मंच पर बैठे उद्योगपतियों को शर्मसार करते हुए मध्यप्रदेश सरकार को ताना मारा कि 45 एकड़ जमीन पर तो वह कबड्डी खेलते हैं।

हर जगह इन्हें आवश्यकता से अधिक जमीन चाहिए और इस जमीन का टाइटिल भी अपने नाम पर रजिस्टर्ड चाहिए और साथ ही मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए दी जाने वाली केंद्र सरकार 150 करोड़ रुपये सब्सिडी भी ये हड़प जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में भी यही बात हुई है .....सरकारी स्कीम में मनमाने परिवर्तन करिए ओर अधिक से अधिक जमीन पर कब्जा कीजिये ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है।

जो जमीन नोएडा में बाबा रामदेव की कंपनी को दी गई, वह पहले कई किसानों को 30 साल के पट्टे पर दी गई थी बिना इजाजत अखिलेश सरकार में लाला रामदेव ने वहाँ 6000 पेड़ कटवा दिए। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है लेकिन यहाँ कोई पर्यावरण प्रेमी इस बात का संज्ञान लेना नही चाहता।

अब आते हैं नवीनतम घटनाक्रम पर ..... बालकृष्ण ने ट्वीट किया कि आज ग्रेटर नोएडा में केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत मेगा फूड पार्क को निरस्त करने की सूचना मिली।

श्रीराम व कृष्ण की पवित्र भूमि के किसानों के जीवन में समृद्धि लाने का संकल्प प्रांतीय सरकार की उदासीनता के चलते अधूरा ही रह गया, पतंजलि ने प्रोजेक्ट को अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्णय लिया।

इस ट्वीट के जवाब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालकृष्ण से देर रात टेलीफोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने संबंधित नीति के तहत उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

अब आप इस खेल को समझिये जो बालकृष्ण खेल रहे हैं। सीधी बात तो यह है कि वह चाहते हैं कि योगी सरकार 50 एकड़ की भूमि के टाइटल पतंजलि के नाम करने के बहाने अधिक से अधिक भूमि का टाइटिल ही पतंजलि के नाम कर दे..... पतंजलि ग्रुप के प्रवक्ता एस के तिजारावाला बता रहे है कि नोएडा में बनने वाले पतंजलि फूड पार्क की जमीन के टाइटल सूट के लिए केंद्र सरकार की ओर से दो बार नोटिस भेजा गया था. लेकिन योगी सरकार की ओर से पतंजलि को टाइटल सूट नहीं सौंपा गया।

अब दबाव में आकर योगी सरकार केबिनेट के बैठक में इस जमीन का टाइटिल सौपने को राजी हो गयी है लेकिन सब मिला जुला खेल है।

ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के मन्दसौर का है जहाँ प्रस्तावित फ़ूड पार्क को बनाने वाली कम्पनी ऐसा ही चाह रही थी जैसे लाला रामदेव चाह रहे हैं लेकिन स्थानीय कलेक्टर ने जमीन का नामांतरण कंपनी के नाम पर करने से इंकार कर दिया ओर इस मामले को लेकर वह हाईकोर्ट भी चले गए , मामला कोर्ट में होने से जब तक इस पर फैसला नहीं होता, फूड पार्क का काम आगे नहीं बढ़ेगा।

लेकिन यह मामला पतंजलि से संबंधित नही था इसलिए यह सम्भव हो पाया। यहाँ तो केंद्र और राज्य सरकारें ओर मीडिया तीनो ही गोदी में बैठे हुए हैं इतनी बात करने की किसी की हिम्मत ही नही है।

कुल मिलाकर सत्तासीन लोगो से सांठगांठ कर देश भर में मेगा फूड पार्क के नाम दोगुनी चौगुनी जमीन को बेहद मामूली दर पर खरीद कर ही पतंजलि इतनी जल्दी सफलता की सीढ़ी चढ़ पाया है इस बात में किसी को शक नही होना चाहिए।

चार साल की उपलब्धि : एक पैसा सस्ता पेट्रोल

गतांक की चीर-फ़ाड़

डा. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 3-9 जून 2018 के अंक में राष्ट्रीय क्षेत्रीय व स्थानीय मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुए हैं। 'मंत्री गोयल काम-काज नहीं, कथा पाखंड तो कर ही सकते हैं-फ़रीदाबाद में मुरारी बापू की राम कथा व सत्ता गठजोड़ का घिनौना प्रदर्शन' लेख में शासक वर्ग व धार्मिक वर्ग के गठजोड़ को पूरा उज़ागर किया गया है। शासक वर्ग को जनता व सत्ता पर नियंत्रण बनाये रखने के लिये धार्मिक वर्ग (ऋषि मुनि व बाबाओं) द्वारा प्राचीन काल से ही सदैव सहायता दी जाती रही है और धार्मिक वर्ग को शासन वर्ग द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। राजनीतिक दलों को इन बाबाओं (आसाराम, रामदेव, रामपाल, राम रहीम, सिद्धदाता आश्रम के पुरूषोत्तमाचार्य आदि) के आशीर्वाद से चुनाव में वोट भी प्राप्त होते हैं। राम कथा आयोजकों तथा बाबाओं का आम लोगों की समस्याओं की तरफ़ कोई ध्यान जाता। ऐसे में कोई पूछने वाला नहीं कि 9 दिनों तक चलने वाले राम कथा आयोजन में जो करोड़ों रुपये खर्च हुये उसका हिसाब क्या है?'कलयुग की चर्चा क्यों नहीं करते मुरारी बापू...'से स्पष्ट है कि इस आयेजन में लोगों की भीड़ किस प्रकार जुटाई गई।

संघ परिवार से सम्बन्धित विभिन्न संगठनों द्वारा लव जिहाद अभियान चलाया जा रहा है, विशेषकर यदि युवक मुस्लिम और युवती हिन्दू हो, तो यथाकथित लव जिहादी युवक को मारने के लिये हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। सरकार व प्रशासन द्वारा भी उस युवक व युवती को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। परन्तु 'सरदार जी तुस्सी ग्रेट हो!' में सब-इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह द्वारा नैनीताल के गिरजा देवी मंदिर में बिना अपनी जान की परवाह किये मुस्लिम युवक को साम्प्रदायिक उन्मादियों के चंगुल से बचाने का प्रशंसनीय व सराहनीय कार्य किया गया है। आशंका है कि कहीं सरकार व प्रशासन गगनदीप सिंह के विरुद्ध ही कोई कार्यवाई न कर दे।

योग गुरू उद्योगपति व व्यवसायी रामदेव ने संघ व प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग से स्वदेशी के नाम से जनता को बेवकूफ़ बनाकर अपना विशाल व्यवसायिक पतंजलि साम्राज्य खड़ा कर लिया है और अन्य कॉरपोरेट घराने उसमें पिछड़ने लगे हैं। पतंजली ने लगभग हर क्षेत्र में अपने विभिन्न प्रोडक्ट्स जैसे क्रीम, पाउडर, साबुन, आटा, बिस्किट, कच्ची घानी का सरसो का तेल, देसी घी, दवाइयां, सिम कार्ड, किंभो मोबाइल एप आदि लांच कर दिए हैं जिनका 'बाबा रामदेव नहीं उद्योगपति रामदेव कहिये, अब रखा टेलिकॉम इंडस्ट्री में कदम' व 'रामदेव सब कुछ बेच सकता है... आपका डेटा चुराने का अब लाया किंभो मोबाइल एप' लेखों में पूरा वर्णन किया गया है। पतंजलि इतना शक्तिशाली हो गया है कि सरकार व प्रशासन सैंकड़ों करोड़ों रुपयों की चोरी करने पर भी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर पाते। इसका नवीनतम उदाहरण है उत्तर प्रदेश की तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार ने पतंजलि को पतंजलि मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिये यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र में ज़मीन अलॉट की थी परंतु पतंजलि द्वारा अलॉटमेंट की शर्तें पूरी न करने के कारण प्रशासन द्वारा आगे कोई कार्यवाई नहीं की गई। इस पर पतंजलि ने उत्तर प्रदेश सरकार को धमकी दी कि वे इस मेगा फूड पार्क को किसी अन्य राज्य में शिफ़्ट कर देंगे, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं रामदेव व आचार्य बालकृष्ण से बात की तथा सभी आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का आश्वासन दिया और फूड पार्क को किसी अन्य राज्य में शिफ़्ट न करने का आग्रह किया।

संघ परिवार से सम्बन्धित लगभग सभी सरकारें दलित व मुस्लिम विरोधी हैं तथा इनके राज्यों में दलित व मुसलमानों का उत्पीड़न होता रहता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो दलितों व मुसलमानों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा मानकर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जब मनचाहे गिरफ़्तार कर लेती है जिसका लेख 'योगी सरकार दलितों-मुसलमानों पर रासुका लगाकर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा बताने पर आमदा' में तथ्यपूर्ण विवेचन किया गया है। इस से योगी सरकार की वास्तविक मन्शा प्रकट होती है।

प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में अपनी पीठ थपथपाने न झूठे आंकड़े पेश करने में माहिर हैं जिसका 'पीएम मोदी ने बहुत लम्बी-लम्बी छोड़ी है, उन्होंने बहुचर्चित मुद्रा योजना के जो आंकड़े पेश किये हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं' तथा 'मोदी सरकार रोजगार के छद्म आंकड़ों को प्रोत्साहित कर रही हैं जिनका परीक्षण नहीं हुआ' में मोदी द्वारा प्रस्तुत झूठे आंकड़ों का तथ्यात्मक पर्दाफ़ाश किया गया है। बड़े उद्योगपतियों के ऋण तथा मुद्रा योजना लोन दोनों के एनपीए हो जाने और भाजपा नेताओं व ज़िला प्रशासकीय अधिकारियों के अनुचित हस्तक्षेप किये जाने के कारण सरकारी बैंकों की आर्थिक दुर्दशा हो रही है तथा आपेक्षित रोज़गार भी पैदा नहीं हो रहे हैं।

मोदी सरकार द्वारा 4 वर्ष पूरे होने पर तथा 2019 के आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अपनी तथाकथित उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। 'खबर (दार) झरोखा-सरकार के चार साल, तर्क तथ्यों के अचार साल हैं' में मोदी व भाजपा के विपक्ष में रहते हुये किए गए झूठे वादे, 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के समय किये गये झूठे लुभावने वादे व आश्वासन, कोयले की कमी, बिजली के उत्पादन का घटना, नई पेंशन स्कीम का झांसा, बैंकों का घाटा, मुद्रा लोन का फ़र्जीवाड़ा, बेरोजगारी आदि का तथ्य पूर्ण विश्लेषण किया गया है। 'कोबरा पोस्ट ने की अपने बहुचर्वित स्टिंग ऑपरेशन 136 की दूसरी किश्त रिलीज' से स्पष्ट है कि अग्रणी मोबाइल बैंकिंग कम्पनी पेटीएम ने पीएमओ के आदेश पर उपभोक्ताओं का निजी डाटा सरकार को लीक किया। चौंकाने वाली बात है कि मोदी सरकार के नोटबंदी के मूव की जानकारी पेटीएम को पहले से थी। इसके अतिरिक्त पेटीएम के संघ परिवार से घनिष्ठ सम्बन्ध होने का दावा किया जा रहा है। आश्चर्य है कि इस रहस्य के सामने आने पर भी राजनीतिक गलियारे में कोई हलचल नहीं है। संघ परिवार व मोदी सरकार के पेटीएम से गठजोड़ के रहस्य का भंडाफ़ोड़ करने के लिये पेटीएम कांड की निष्पक्ष व गहन जांच करने की आवश्यकता है।

जनता की समस्याओं को नेपथ्य में धकेलकर मोदी द्वारा नए मुद्दे उठाने पर 'मुझसे लड़ो',भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के बारे में झूठा अनर्गल प्रचार करने पर 'लोकतंत्र के द्रष्टा! प्रथम सेवक/ प्रथम झूठिया' तथा तेल की बढती कीमत के सन्दर्भ में पेट्रोल का दाम एक पैसा सस्ता करने पर 'एक पैसा सस्ता हुआ पेट्रोल-उसी एक पैसे का डाल दो' कार्टूनों के माध्यम से मोदी की नीतियों पर उपयुक्त व्यंग्य किया गया है।